

राफेल विरोधी राग

भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल शांति है। युद्ध में हार और जीत के आकलन के बीच कुछ कहानियां राफेल की भी सुनवाई जा रही हैं। खासकर फ्रांस से प्राप्त राफेल जेट को लेकर अमेरिकी मीडिया में बहुत सारी बातें बिना सिर-पैर की हो रही हैं। पाकिस्तान ने 7 मई को यह दावा किया था कि उसने तीन राफेल समेत भारत के पांच जंगी जहाजों को गिरा दिया। पाकिस्तान अपने इन दावों के लेकर खुद ही हंसी का पात्र बना, उसके रक्षामंत्री से एक विदेशी मीडिया ने जब पूछा कि सुबूत क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सोशल मीडिया में सब चल रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पार्लियामेंट में यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान चाहता तो 12 भारतीय जेट गिरा सकता था, मेहरबानी कर के पांच ही गिराया। जिस देश के हुक्मरान इतने नादान और मूर्ख हों, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है। अब यही मूर्खता विदेशी मीडिया के कुछ अन्य प्लेटफार्म से भी हो रही है।

‘द वाशिंगटन पोस्ट’, ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ और ‘सीएनएन’ चैनल जैसे बड़े मीडिया हाउस पाकिस्तान के भोपू बने हैं। वह कुछ मनगढ़ूंत खबरों के जरिए अमेरिकी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषण की जरूरत है। कहीं यह अमेरिकी हथियार के सौदागरों के एजेंट तो नहीं बन रहे हैं। सीएनएन ने राफेल के गिरने की खबर पाकिस्तानी खाा सूत्रों से चला दी, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने पांच भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिनमें तीन राफेल जेट, एक मिग-29 और एक सुखोई 30 फाइटर जेट शामिल हैं। अपनी खबर को पुष्ट दिखाने के लिए सीएनएन ने एक कथित अनजान फ्रांसीसी खुफिया अधिकारी का हवाला भी दे दिया, जिसने कथित रूप से यह स्वीकार किया कि भारतीय वायु सेना को दिये गये राफेल लड़ाकू विमानों में से एक को पाकिस्तान ने मार गिराया है।

दो अनजाने अमेरिकी अधिकारियों का हवाले से यह भी खबर चली कि चीन निर्मित पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने कम से कम दो भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया। इस मामले में ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ भी पीछे नहीं रहा। इस अमेरिकी मीडिया ने भी वही अज्ञान स्रोत का सहारा लिया और खबर चला दी कि भारत ने कम से कम दो विमान खो दिये हैं। बस, उसने राफेल का नाम नहीं लिया। ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने तो एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ का भी हवाला दे दिया है, जो कबौल अखबार के यह स्वीकार करता है कि भारत ने मिराज-2000 और राफेल विमान खो दिये हैं। मालूम हो कि राफेल और मिराज दोनों दोनों फ्रांसीसी हैं।

अमेरिकी मीडिया के इस रुख पर सवाल उठाना लाजिमी है कि जब अभी तक पाकिस्तान ने जहाज गिराये जाने के कोई ठोस सुबूत नहीं दिये हैं और ना भारत ने इस संबंध में कोई पुष्टि की है। फिर अमेरिकी मीडिया अज्ञात स्रोतों का हवाला देकर इतनी बड़ी खबर क्यों चला रहा है? क्या उनके उद्देश्य कुछ और हैं? कहीं यह अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मार्केटिंग का फंडा तो नहीं है। यह सबको खबर है कि भारत समेत कई देश इस समय लड़ाकू विमानों की खरीदारी के लिए इच्छुक हैं। दुनिया एयरोस्पेस बाजार बहुत बड़ा है और अरबों खरबों डॉलर के सौदे होने हैं। चूँकि अमेरिका भी लड़ाकू विमानों का सौदागर है और वह अपने एफ-35 जेट के लिए कई देशों में लामबंदी कर रहा है। इसलिए उसके लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसी राफेल ही है। राफेल के खिलाफ खबरें उसी कंपटीशन का हिस्सा हो सकती हैं।

अपने खिलाफ जारी वैश्विक षड्यंत्रों को समझ पायेगा भारत ?

कमलेश पांडेय

पहले अमेरिका और सोवियत संघ, फिर अमेरिका एवं रूस और अब अमेरिका व चीन के बीच जो दुनिया का थानेदार बनने की होड़ मची है, उससे गुटनिरपेक्ष देश भारत के हित गहरे तक प्रभावित हुए हैं। यह हमारे देश के नेताओं और अधिकारियों की गलत और पक्षपाती नीतियों का ही दुष्परिणाम है कि भारत को न चाहते हुए भी कभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तो कभी आंतरिक भूभाग पर युद्ध जैसे हालातों से गुजरना पड़ता है, जिसमें धन-जन की भारी हानि होती है।

दरअसल, हमारे देश में बढ़ते साम्प्रदायिक विवाद, जातीय विवाद, क्षेत्रीय विवाद आदि का मौलिक कारण यह है कि विदेशी तिकड़मों के चलते आजादी से पहले हमारे ‘मानवीय मूल्यों’ से ‘सियासी बलात्कार’ हुए हैं, और उसके बाद उप्पे पक्षपाती ‘संवैधानिक मूल्यों’ से भी ‘अनैतिक प्रशासनिक व न्यायिक बलात्कार’ हुए हैं! जहां प्रशासनिक और न्यायिक विवेक का गुल्लममुखुल्ला उल्लंघन यह कहते हुए किया गया कि हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है अथवा उसकी मूल भावना यह है। वहां पर जीवन एवं प्रशासनिक मूल्यों का भी घोर अभाव मसहूस किया गया है।

तुलूख अनुभव बताता है कि जब-जब कोई ‘राजा या उसका मंत्री’ व्यावहारिकता की जगह परम्परा की दुहाई देता है और ‘जनता या पड़ोसी राजाओं’ से उसका तालमेल नहीं बैठता तो वह नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बाह्य आक्रमणकारियों को अस्तुष्ट जनता का साथ मिल जाता है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई वृतांत



भरे पड़े हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों या ब्रिटिश कम्पनियों को यहां के हिन्दू राजाओं द्वारा एक दूसरे को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचकर बुलाया गया और जब वो हिन्दू भारतीयों की कमजोरी पकड़ लिए तो यहां का शासक बन बैठे। जिससे लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय गुलामी का दंश झेलते रहे और बमुश्किल आजाद हुए लेकिन हमारे नेताओं की रस्साकशी ने फिर उसी विभाजनकारी घृणित सोच का सहज शिकार बना दिया, जो आज भी जारी है।

वहीं, कंग्रिसियों, वामपंथियों, समाजवादियों, जातिवादी क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रवादियों के जनतांत्रिक सत्ता संघर्ष में ये तमाम दुर्गुण मसहूस किए जा सकते हैं। इसी बीच वर्ष 1990 के दशक से भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की आड़ में जो हिंसक-प्रतिहिंसक पूंजीवादी एजेंड सियासी आवरण में चलवाया जा रहा है, उसके पीछे निहित उद्देश्य वश इतना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के नेतृत्व में जो उपनिवेश बनाये गए थे, वो अब सूचना व

तकनीकी क्रांति के बाद अमेरिका के नेतृत्व में तथाकथित नए उपनिवेश में शामिल हो जाएं।

हालाँकि इस बीच पूर्वी देशों के साम्यवादी रूस और चीन के उभार ने अमेरिका-इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देशों की जोड़ी के लिए ‘भस्मासुर’ का कार्य किया, जिससे निपटने के लिए भारत का पश्चिमी खेमे या पूर्वी खेमे से जुड़ना पहली शर्त है जबकि गुटनिरपेक्ष भारत सभी धड़े से समान दूरी बनाकर रखता आया है और तीसरी दुनिया के देशों को नेतृत्व देता है। इसके बावजूद समाजवादी सोच वाली कंग्रिस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस से और पूंजीवादी सोच वाली भाजपा के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से मजबूत रिश्ते कायम किये।

वहीं, पहले वित्तमंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर डॉ मनमोहन सिंह ने अमेरिकी शह पर व भारत के कारोबारियों की कीमत पर, चीन से कारोबारी सम्बन्ध मजबूत किए, जिसकी हवा उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही निकलनी शुरू हो चुकी थी, जो 2014 में

रामस्वरूप रावतसरे

भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हुआ संघर्षविराम चार घंटे से भी कम समय में टूट गया। पाकिस्तान ने शनिवार रात को जम्मू-कश्मीर से लेकर गुजरात तक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किये, हालाँकि, भारत ने इन ड्रोन हमलों को विफल कर दिया। इससे अमेरिका के विश्वास को जरूर धक्का लगा है। अमेरिका ने दावा किया था कि उसकी मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद भारत और पाकिस्तान में संघर्षविराम हुआ है। इसका क्रेडिट खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लिया है। ऐसे में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सोधे अमेरिका के लिए बेइज्जती माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुई वार्ता के बाद भारत और पाकिस्तान

अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत संघर्ष में पाकिस्तान से उलझ जाए। यह क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता था। जानकारी के अनुसार अमेरिका भारत के साथ बहुत जल्द एक समझौता करने वाला है। किसी भी तरह का तनाव भारत में निवेश के माहौल को बिगाड़ सकता था।

‘तत्काल और पूर्ण’ संघर्ष विराम पर सहमत हो गये हैं। उन्होंने साथ ही दावा किया कि ऐसा अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ता के कारण संभव हो सका है।

सरकारी सूत्रों ने हालाँकि बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का मामला सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच तय हुआ था। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) ने भारतीय डीजीएमओ से फोन पर बातचीत की जिसके बाद



चर्चा हुई और सहमति बनी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इस्हाक डार ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम की पुष्टि की।

जानकारों की मानें तो भारत के हमले से नूर खान एयरबेस के तबाह होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गये थे और वो भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे जबकि उस वक्त तक भारत ने अपने काफी कम तबाही मचाने वाले हथियारों का ही इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था कि भारत अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार को तबाह करने वाला है। इसी बीच अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन करते हैं और उसके बाद सीजफायर का ऐलान हो जाता है। अखिर टेलीफोन पर जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहा था, ऐसी क्या ‘खतरनाक खुफिया’ जानकारी थी, जिसे जानने के बाद भारत सीजफायर के लिए तैयार होता है?

सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले इसका खुलासा किया है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी थी जो काफी खतरनाक बताई जा रही है। ये जानकारी इतनी संवेदनशील थी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, जिसने ठीक एक दिन पहले कह दिया था कि उसे इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, उसे अचानक बीच में आना पड़ा और सीजफायर के लिए भारत से बात करनी पड़ी। बताया जा रहा है



कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है, संभावित तौर पर एक परमाणु युद्ध की आशंका तक पहुंच सकती थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टेलीफोन किया और उस खुफिया जानकारी को देने के बाद उनसे पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत के जरिए सीजफायर का समाधान निकालने का प्रस्ताव रखा। उनके टेलीफोन का मकसद भारत को एक सीधे युद्ध से बचने की सलाह दी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि ‘खुफिया जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले जेडी वेंस तत्काल डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे थे और उनसे जानकारीयां शेयर की और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टेलीफोन किया।’ इस दौरान जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि ‘अमेरिका का आकलन है कि अगर संघर्ष दो दिनों तक और चलता है तो ये युद्ध नाटकीय अंजाम तक बढ़ सकता है।’ हालाँकि अमेरिकी अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि ‘वो खुफिया जानकारी क्या था और युद्ध के नाटकीय अंजाम तक बढ़ने का क्या मतलब था।’

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस के तबाह होने के बाद पाकिस्तान बहुत ज्यादा डर गया था और उसे लग रहा था अब भारत उसके हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करने वाला है। नूर खान एयरबेस, पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे

संवेदनशील एयरबेस है और भारत ने यहां पर डीप स्ट्राइक किए थे जिस के कारण पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम भारतीय हथियारों को बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे जिससे भारतीय हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था जबकि पाकिस्तान के मिसाइल भारत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे जिससे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गये थे और वो किसी तरह से युद्ध से बाहर निकलना चाहता था।

जानकारों की माने तो अमेरिका का हस्तक्षेप बिना किसी कारण के नहीं था। पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते संघर्ष से अमेरिका के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते थे। अस्थिरता के कारण व्यापार और निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता था। इसके अलावा, क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से तेल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती थीं। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अमेरिका पर मंदी के बादल छाए हुए हैं। ऐसे समय में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को और बढ़ा सकता था। इससे अमेरिका सहित तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। अपनी तरफ?की से भारत ??लोबल ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के लिए वह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी है। ऐसे हालात में अमेरिका के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आर्थिक रूप से अधिक फायदेमंद है। आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। वह पहले ही बर्बाद मुल्क है।

अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत संघर्ष में पाकिस्तान से उलझ जाए। यह क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता था। जानकारी के अनुसार अमेरिका भारत के साथ बहुत जल्द एक समझौता करने वाला है। किसी भी तरह का तनाव भारत में निवेश के माहौल को बिगाड़ सकता था। वहीं पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के भी कई एजेण्डे है जिन्हें वह आने वाले समय में पूरा करना चाहेंगा। इसलिए उसे उसकी ही जरूरत है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि सता में कौन रहता है किसका खम्चा होता है। इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो बस उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने से है। इसके लिए वह किसी भी स्तर तक जा सकता है ।

उपर और उनकी पार्टी पर भारी पड़ी। इस प्रकार देखा जाये तो कभी भी अखंड भारत और मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद नहीं रखी गयी और अल्पमत-बहुमत के जनतांत्रिक हिसाब से भारतीयों को परस्पर लड़ना गया, जिसकी भारी कीमत अब हिंदुस्तानी अवाम चुका रही है।

वहीं, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तो उन्होंने अतीत की गलतियों को नए सिरे से सुधारने की एक सकारात्मक पहल की। लेकिन विदेशी प्रलोभनों और दबाव में भारत का प्रतिपक्ष ‘ईंडिया गठबंधन’ बनाकर उनके ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो गया। बावजूद इसके उन्होंने रूस, अमेरिका, जापान, इजरायल, फ्रांस आदि देशों से मजबूत सम्बन्ध स्थापित किये और भारत के पड़ोसियों की नकेल कसी। यही वजह है कि पहले अमेरिका और अब चीन के मार्फत पाकिस्तान को साधकर भारत के खिलाफ भड़काया गया।

एक तरफ रूस, अपने पड़ोसी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ इजरायल, अपने पड़ोसी फिलिस्तीन के साथ संघर्षरत है और तीसरा मोर्चा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खोल दिया है। वह भी ऐसे समय में जबकि भारत के दो मजबूत सहयोगी और शुभचिंतक अपनी अपनी सीमाओं पर युद्ध लड़ रहे हैं। यह अमेरिकी और चीनी पूंजीपतियों की आंतरिक चाल है, ताकि इनके हथियारों को

नए-नए बाजार मिलते रहें। ऊपर से तो इनकी टैरिफ वार चलती रहती है, लेकिन अंदरखाने के दांबपेंच पूरी दुनिया के लिए शोष का विषय है।

यही वजह है कि भारत को इससे ज्यादा सावधान रहना होगा। क्योंकि पहले हमारे खिलाफ कोरोना महामारी की सांजिश रची गई, फिर लदाख़ पर चीनी दबाव बढ़ा। उस संकट से निकले हुए अभी 6 माह भी नये हुए हैं कि पाकिस्तान प्रेरित कश्मीर संकट पैदा कर दिया गया। अमेरिका और चीन के कारोबारी सम्बन्ध किसी से छुपे हुए नहीं हैं, वहीं दुनिया का नया थानेदार बनने की इनकी शतरंज की चाल पर

भारत-रूस-इजरायल जैसे संघर्षरत अन्य देश सिर्फ मोहरा मात्र हैं, जिन्हें समझने की और एहतियाती रणनीति बनाने की जरूरत है।

जिस तरह से भारत ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें पाकिस्तान

को 2.3 अरब डॉलर का नया कर्ज देने की बात की गयी थी। क्योंकि भारत का कहना है कि यह पैसा पाकिस्तान सरकार सीमापार आतंकवाद फैलाने में इस्तेमाल कर सकती है। इस बारे में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत ने आईएमएफ बोर्ड की बैठक में हिस्सा तो लिया, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लिया। भारत ने कहा कि अगर ऐसे देश को बार-बार कर्ज दिया जाता है, तो इससे वैश्विक मूल्यों का

मजाक बनता है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी जोखिम में आ जाती हैं।

बावजूद इसके, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 9 मई 2025 दिन शुक्रवार को पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की तुरंत किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी पाकिस्तान के पीएमओ ने दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर कहा कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर की किस्त को मंजूरी मिलना भारत की दबाव बनाने की रणनीति की असफलता है। यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया। इससे साफ है कि जिस अमेरिका और चीन ने पारस्परिक गुप्त सांठगांठ से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काया है, वही लोग अब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उसे धन भी दिलवा रहे हैं, ताकि ‘चोर दरवाजे’ से वह सैन्य साजोसामान खरीद सके और भारत के मुकाबले हथियारों की होड़ पैदा की जा सके।

वैश्विक मामलों के जानकार बताते हैं कि रूस और चीन मिलकर जिस तरह से अरब और इस्लामिक मुल्कों में अमेरिका को घेर रहे हैं और यूरोप से उसकी रणनीतिक दूरी बढ़वा रहे हैं, उसी तरह से अमेरिका भी उन्हें घेरने की चाल चल रहा है। इससे भारत के बचाव पाकिस्तान की ओर झुकाव रखना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि वहीं से अफगानिस्तान, तुर्की और अरब देशों के अलावा चीन को संतुलित रखने में भी वह मददगार साबित होगा, पूर्व की तरह क्योंकि भारत उसके बस में रहने वाला नहीं है।

आत्मबोध

विभिन्न मन्त्र और उनके लाभ

ॐ गं गणपतये नमः : इस मंत्र के जाप से व्यापार लाभ, संतान प्राप्ति, विवाह आदि में लाभ प्राप्त होता है।

ॐ ह्रीं नमः : इस मन्त्र के जाप से धन प्राप्ति होती है।

ॐ नमः शिवाय : यह दिव्य मन्त्र जाप से शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण होता है।

ॐ शांति प्रशांति सर्वं क्रोधोपशमनि स्वाहा : इस मन्त्र के जाप से क्रोध शांत होता है।

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः : इस मंत्र के जाप से सफलता प्राप्त होती है।

ॐ क्लीं ॐ : इस मंत्र के जाप से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और बिगड़े काम बनते हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय : इस मंत्र के जाप से आकस्मिक दुर्घटना से मुक्ति मिलती है।

ॐ ह्रीं हनुमते रुद्रात्म कायै हुं फटः : सामाजिक रूतबा बढ़ता है और पदोन्नति प्राप्त होती है।

ॐ हं पवन बंदनाय स्वाहा : भूत प्रेत और ऊपरी हवा से मुक्ति प्राप्त होती है.

ॐ भ्रां भ्रीं भौं सः राहवे नमः : परिवार में क्लेश दूर होता है और शांति बनी रहती है।

ॐ नमः शिवाय : इस मंत्र के जाप से आयु में वृद्धि होती है और शारीरिक रोग दोष दूर होते हैं।

ॐ महादेवाय नमः : सामाजिक उन्नति व धन प्राप्ति के लिए यह मन्त्र उपयोगी है।

ॐ नमो भगवते रुद्राय : मान सम्मान की प्राप्ति होती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। (सम्पाप्त)

पीआरजीआई/आरएनआई पंजियन संख्या : 52413/1991(टाइल कोड : JHAHIN00860),पोस्टल रजिस्ट्रेशन संख्या : RN/260/2020-22.
अध्यक्ष व प्रधान संपादक: **बलबीर दत्त**.
देश प्राण (समाचारपत्र, शीर्षक व ट्रेडमार्क) संस्थापक व स्वत्वाधिकारी **बलबीर दत्त**
के लिए प्रकाशक **रोहित दत्त *** द्वारा 4/A, तारा टावर, होटल महाराजा के सामने, रेडियम रोड, कचहरी चौक, रांची - 834001 से प्रकाशित तथा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस (डीबी कॉर्प लिमिटेड), 535/1272, लालमुटवा, रांची से मुद्रित.
फोन नंबर: 0651 2361181, 0651 2361182.
ईमेल: contact@deshpran.in (*पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार).



LIC/AR/19-20/40/HIN

